

Title: Need to hold election in Cantonment Boards and also not to increase the water cess in these areas.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, लगभग ढाई साल पहले देश भर के सारे कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव होने थे, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम कैंटोनमेंट बोर्डों (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये लोग भी नहीं लिख पाएंगे इतने हल्ले में। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am going to permit her after these notices are over. Her notice is not on Adjournment Motion. आपका भी नोटिस है मगर जीसे आबर में मैं उनको प्रायॉरिटी दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं? आपको क्या हो गया है, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please keep quiet now. Let everybody get an opportunity.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लाल मुनी जी, आप बैठिये। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है, आप प्लीज़ बैठिये। ऐसे सदन कैसे चल सकता है? रघुवंश प्रसाद जी, क्या हर प्रश्न का जवाब देने की जरूरत है? आप बहुत अच्छे सदस्य हैं, बहुत अच्छे मान्यवर सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लाल मुनी जी, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है, आप क्यों खड़े रहते हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, आज से ढाई साल पहले जब देश के सारे कैंटोनमेंट बोर्डों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उस समय भारत सरकार ने यह कहा था कि हम कैंटोनमेंट बोर्डों के संविधान में संशोधन करना चाहते हैं और इसलिए एक साल के लिए सारे निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। एक साल के अंदर भारत सरकार उन कैंटोनमेंट बोर्डों के संविधान में कोई संशोधन नहीं कर पाई। फिर उसने एक साल का कार्यकाल बढ़ा दिया कि अभी तक चूंकि संशोधन नहीं हो पाए हैं इसलिए कैंटोनमेंट बोर्डों के कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाए जाते हैं। दो साल बीतने के बाद भी भारत सरकार संविधान में कोई भी संशोधन नहीं कर पाई है। जब संशोधन नहीं कर पाई तो उसने पूरे देश के कैंटोनमेंट बोर्डों को भंग कर दिया और भंग करके यह आश्वासन दिया कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा और जब तक चुनाव नहीं होगा, तब तक नए बोर्डों की हम संरचना कर रहे हैं जिसमें

* Not Recorded.

एक एक जन प्रतिनिधि हर कैंटोनमेंट बोर्ड में सरकार नॉमिनेट करेगी। आज छः महीने हो गए लेकिन किसी भी कैंटोनमेंट बोर्ड में किसी जन प्रतिनिधि का नॉमिनेशन नहीं हुआ है। परिणाम यह निकल रहा है कि केवल चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर और वहां का लोकल सैनिक अधिकारी, ये दो मिलकर देश भर के कैंटोनमेंट बोर्डों में जो चाहे वह कर रहे हैं। मैं अपने कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड का उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहां इन तीन महीनों के अंदर वहां के कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ और लोकल ब्रिगेडियर ने मिलकर जल कर में दस गुना बढ़ोतरी कर दी है।

अध्यक्ष महोदय, एकदम 10 गुना बढ़ोतरी जलकर में की गई है। इसके अलावा जिन मकानों के टैक्स के पहले ऐसैसमेंट हो चुके हैं, उनके री-ऐसैसमेंट किए जा रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले लोगों का कई प्रकार से उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। अतः मेरी रक्षा मंत्री महोदय से मांग है कि जब तक जनप्रतिनिधियों के चुनाव न हो जाएं, तब तक कैंटोनमेंट बोर्डों में कहीं भी किसी भी तरह की टैक्स में बढ़ोतरी न की जाए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएं। चुनाव होने के बाद ही संविधान में यदि किसी तरह का परिवर्तन करना हो या संशोधन करना हो, वह किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी, आपकी बात पूरी हो गई। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे पास और लोगों के नाम भी हैं। मैं उन्हें भी बोलने हेतु समय देना चाहता हूँ।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, यह बहुत गम्भीर सवाल है। मेरी बहुत अहम मांग है कि कैंटोनमेंट बोर्डों में किसी भी प्रकार का टैक्स न बढ़ाया जाए, मकानों के टैक्स के री-ऐसैसमेंट न किए जाएं और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अभाव में कैंटोनमेंट बोर्डों में अधिकारियों द्वारा लाखों-करोड़ों रुपयों का घपला किया जा रहा है। जो अधिकारी जहां बैठा है, वह जैसा चाहता है, जनता के साथ वैसा व्यवहार करता है और धन का घपला करता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय से पुनः मांग है कि इस तरह के टैक्सों की बढ़ोतरी न की जाए और जब तक जनप्रतिनिधि न चुने जाएं तब तक नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन न किया जाए और तब तक जलकर में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी न की जाए। (व्यवधान)